प्रेषक,

मनीषा पंवार, सचिव ,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, नन्रखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक)

देहरादूनः दिनांकः ७ र जून, 2013

विषयः वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या—रा0प0का0/80/MDM-08 (बजट)/2013—14 दिनांक 9.5.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2013—14 में मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित संलग्नक—01 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान—11 (सामान्य), अनुदान स्र्व 30 (एस0सी0एस0पी0) एवं अनुदान स्र्व 31(टी0एस0पी0) में कुल धनराशि रू0 37,91,13,000—00 (रूपये सैंतीस करोड़ इक्यानवे लाख तेरह हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) वित्त विभाग के शासनादेश सँ० 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.3.2013 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा

रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि को इस प्रतिबन्ध के साथ अवमुक्त किया जा रहा है कि गत वर्षों / इस वर्ष अवमुक्त राशि के सापेक्ष वास्तव में व्यय नहीं हुई धनराशि जो कदाचित स्कूलों के खाते में पड़ी होगी, का विवरण प्राप्त कर उसके सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट की जाय। साथ ही किचन कम स्टोर निर्माण के लिये अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय व भौतिक प्रगति भी शासन को प्रस्तुत की जाय।

(3) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया

जायेगा।

(4) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जांयेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(5) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(6) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(7) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं। (8) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

02— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—01—प्रारम्भिक शिक्षा व 4202—01 के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबंधित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

03— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 25 (P)/XXVII(3)/2013-14 दिनांक 31.3.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)

सचिव।

सॅ0 567 (i)/XXIV(1)/2013-05/2013 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
- 02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी—1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।

03. मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी देहरादून।

04. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, ननूरखेड़ा देहरादून।

05. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड

06. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)

07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।

08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।

10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से.

्र (सुनील श्री पांथरी) उप सचिव।